डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 नवम्बर, 2022, डिस्पेच दिनांक 16 नवम्बर, 2022

| वर्ष 66 | अंक 12 | भोपाल | 16 नवम्बर, 2022 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

किसानों की आय को दोगुना करने उत्पादन भी बढ़ाना होगा - मुख्यमंत्री

कृषि सिंचाई रकबे में की जा रही है निरंतर वृद्धि
म.प्र. में नरवई से भूसा बनाने की योजना लायेंगे
किसानों के लिये भाग्यविधाता साबित होगा कृषि मेला

नई कृषि टेक्नोलॉजी से किसान अपने आपको मजबूत करें - केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर
मुरैना में 3 दिवसीय कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का शुभारंभ

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के किसानों की आय को दोगुना करने के संकल्प की सिद्धि के लिए उत्पादन भी बढ़ाना होगा और लागत को कम करना होगा। इस दिशा में मध्यप्रदेश सरकार जहाँ एक ओर सिंचाई का रकबा लगातार बढ़ा रही है, वहीं किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। किसानों के लिये आज का कृषि मेला भाग्यविधाता साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान मुरैना जिले में तीन दिवसीय 'कृषि मेला एवं प्रदर्शनी' के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छोटे किसानों को आर्थिक मदद के लिये जहाँ एक ओर प्रधानमंत्री श्री मोदी एक साल में तीन किस्तों में 6 हजार रूपये देते हैं, वहीं मध्यप्रदेश सरकार भी अपनी ओर से इन किसानों को साल में 2 किस्तों में 4 हजार रूपये दे रही है। इस प्रकार किसान को एक साल में 10 हजार रूपये की सहायता मिल रही है। प्रदेश के किसानों

को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी अब तक 2 लाख 12 हजार करोड़ रूपये मिल चुके है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में फसल बीमा योजना में किसानों के खातों में 7618 करोड़ रूपये डाले गये हैं। इतनी बड़ी राशि किसी राज्य के किसानों को नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य भी 2125 रूपये प्रति क्विंटल कर किसानों को संबल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिये देश और मध्यप्रदेश में अनेक नवाचार के साथ नई कृषि तकनीक भी अपनाई जा रही है। परम्परागत खेती से हट कर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

म.प्र. में नरवई से भूसा बनाने की योजना लायेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों द्वारा नरवई को जलाने की प्रथा को खत्म करने के लिये एक नई योजना लेकर आ रही है। इस योजना में मशीन द्वारा नरवई से भूसा तैयार किया जाएगा। मशीन खरीदने के लिये छोटे किसानों को 50 प्रतिशत और बड़े किसानों को 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। नरवई से तैयार भूसा गो-माता के काम आयेगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। हर 10 से 20 गाँव के बीच केन्द्र बनाये जायेंगे। साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटर का भी निर्माण होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में नौजवानों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उन्हें खाद्यान्न सामग्री वितरण व्यवस्था से भी जोड़ा जा रहा है। सामग्री प्रदाय केन्द्रों से अब ठेकेदारों के स्थान पर नौजवान अपनी गाड़ियों से खाद्यान्न सामग्री का वितरण करेंगे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

किसानों को खाद के लिए लाइन न लगानी पड़े : श्री चौहान

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को सहज ढंग से बिना परेशानी के खाद मिले, उन्हें लाइन न लगानी पड़े, यह सुनिश्चित करें। उर्वरक की उपलब्धता है, वितरण व्यवस्था की जहाँ कमी है, उसे दूर किया जाये। सभी कलेक्टर्स व्यवस्था करें कि किसानों को उर्वरक लेने के लिये लाइन न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख एल मंडाविया से पूर्ण सहयोग मिला है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज सुल्तानपुर से लौटने के बाद रात्रि में निवास से वीसी द्वारा उर्वरक वितरण समस्या वाले कुछ जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा की। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की इन जिलों से हुई चर्चा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सतना,

राजगढ़, सागर, और नीमच जिलों के कलेक्टर्स से खाद की उपलब्धता, वितरण केंद्र संख्या और वितरण व्यवस्था के संबंध में बातचीत कर निर्देश दिए। कटनी कलेक्टर ने बताया कि बैंकर्स सहयोग कर रहे। शाम 4 की जगह शाम 5:30 बजे तक वितरण का प्रबंध किया गया है। किसानों से प्राप्त राशि के संबंध में बैंक देर शाम तक वित्तीय व्यवहार कर रहे। मुख्यमंत्री ने यह व्यवस्था अन्य जिलों में भी करने के निर्देश दिए।

अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता दमोह से वीसी में शामिल हुए। उन्होंने सागर, छतरपुर और दमोह जिलों में उर्वरक वितरण की व्यवस्थाएँ दौरा कर देखी हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश

- कहीं भी ब्लैक न हो खाद।
- किसान को कहीं जबरन खाद न दें।
- कलेक्टर्स भ्रमण करते रहें।
- किसी भी जिले में किसानों को लाइन न लगानी पड़े।
- जिलों में खाद वितरण सुचारू रहे, जहाँ आवश्यक हो विकेंद्रीकरण किया जाए।
- किसानों को अधिक दूरी से खाद लेने न आना पड़े।

प्रदेश में उर्वरक की व्यवस्था

- केन्द्र सरकार द्वारा माह नवम्बर 2022 के लिए यूरिया का आवंटन 7 लाख मीट्रिक टन (285 लाख मेटन स्वदेशी एवं 4.15 लाख मीट्रिक टन आयातित) एवं डीएपी का आवंटन 1.94 लाख मीट्रिक टन (0.20 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी एवं 1.74 लाख मेट आयातित) दिया गया है। माह नवम्बर, 2022 के लिए 4.15 लाख मीट्रिक टन आयातित यूरिया का आवंटन दिया गया है।
- 11 नवम्बर की स्थिति में यूरिया 1.89 लाख मीट्रिक टन ट्रांजिट सहित, डीएपी 1.33 लाख मीट्रिक टन ट्रांजिट सहित एवं एनपीके ट्रांजिट सहित 52 हजार मीट्रिक टन प्राप्त है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

खाद वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाने करें तकनीक का पूरा उपयोग : मुख्यमंत्री

प्रदेश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता, वितरण में असंतुलन न हो

कंट्रोल रूम निरंतर कार्य करे, आँकड़े भी सामने लाए जाएँ

जिला स्तर पर कलेक्टर्स किसानों तक पहुँचाएं सही जानकारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खाद वितरण की समीक्षा की

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद वितरण की ऐसी व्यवस्था करें कि कहीं भी खाद प्राप्त करने के लिए किसानों को लाइन न लगाना पड़े। उपलब्धता के बाद यह सुनिश्चित करें कि वितरण की व्यवस्था भी सही रहे। केन्द्र सरकार से निरंतर आवंटन प्राप्त हो रहा है। खाद की कोई कमी नहीं है। वितरण का असंतुलन नहीं होना चाहिए। यह जानकारी भी किसान तक पहुँचे। खाद वितरण के सुचारू प्रबंध मैदान में दिखना चाहिए। कंट्रोल रूम से निगाह रखते हुए प्रतिदिन की जानकारी सामने लाई जाए। व्यवस्था में दोषी लोगों को जेल भेजने की कार्यवाही हो। प्रदेश में खाद वितरण के 262 अतिरिक्त काउंटर प्रारंभ किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से खाद और उर्वरक का वितरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि गड़बड़ी करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाएँ। समय पर वितरण के साथ ही सोशल मीडिया से किसानों को आँकड़ों सहित वास्तविक स्थिति की जानकारी जिला स्तर पर दी जाए। इसके लिए कलेक्टर्स आवश्यक व्यवस्थाएँ करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बोवनी कार्य की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके परिश्रम की पूरी कीमत मिलना चाहिए। विशेष रूप से मंडियों में आने वाले सब्जी उत्पादकों को बिचौलियों और व्यापारियों द्वारा अनुचित लाभ लेने से बचाने पर भी ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज शाम निवास कार्यालय में प्रदेश में खाद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री के.सी. गुप्ता, आयुक्त सहकारिता श्री संजय गुप्ता और प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित थे।

प्रदेश का खाद परिदृश्य

बैठक में बताया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा माह नवम्बर-2022 के लिए यूरिया का आवंटन सात लाख मी. टन (2.85 लाख मी. टन स्वदेशी एवं 4.15 लाख मी. टन आयातित) एवं डीएपी का आवंटन 1.94 लाख मी. टन (0.20 लाख मी. टन स्वदेशी एवं 1.74 लाख मी. टन आयातित) दिया गया है। माह नवम्बर 2022 के लिए 4.15 लाख मी. टन आयातित यूरिया का आवंटन दिया गया है, जिसके विरूद्ध केन्द्र सरकार द्वारा 60 हजार मी. टन का आवंटन दिया गया है। दिनांक 5 नवम्बर 2022 की स्थिति में यूरिया 1.20 लाख मी. टन ट्रांजिट सहित, डीएपी 0.83 लाख मी. टन ट्रांजिट सहित एवं एनपीके ट्रांजिट सहित 0.34 लाख मी. टन प्राप्त है। दिनांक 4 नवम्बर 2022 की स्थिति में यूरिया का स्टॉक 2. 23 लाख मी. टन, डीएपी का स्टॉक 1.52 लाख मी. टन एवं एनपीके का स्टॉक 1.14 लाख मी. टन है।

बताया गया कि गत वर्ष 30 नवम्बर, 2021 तक विक्रय मात्रा के अनुसार अनुमान के आधार पर दिनांक 4 नवम्बर 2022 तक यूरिया 32 जिलों में, डीएपी 41 जिलों में, एनपीके 34 जिलों में और डीपएपी +एनपीके का 42 जिलों में भण्डारण कर लिया गया है। विपणन संघ ने माह नवम्बर के लिए 175 यूरिया के रेक और 78 रेक डीएपी की माँग की है, जिसके विरूद्ध एक नवम्बर से 4 नवम्बर 2022 तक 23 यूरिया की रेक और 15 डीएपी की रेक ट्रांजिट सहित मिल चुकी है। विपणन संघ के 240 डबल लॉक केंद्र से नगद वितरण प्रारंभ हो चुका है। भीड़ वाले डबल केंद्रों पर अतिरिक्त केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। कुल 90 केंद्रों से विक्रय प्रारंभ है, शेष विक्रय केंद्र अगले दो दिन में 7 नवम्बर तक प्रारंभ हो जाएंगे।

बताया गया कि प्रदेश में मार्केटिंग समितियों के 105 विक्रय केंद्र प्रारंभ हैं। विपणन संघ के डबल लॉक केंद्रों से एक अक्टूबर से अभी तक 68 हजार मी. टन यूरिया और 61 हजार मी. टन डीएपी को बेचा जा चुका है।

माह अक्टूबर-2022 का यूरिया का आवंटन 6 लाख मी. टन है, जिसके विरूद्ध 3.64 लाख मी. टन यूरिया ट्रांजिट सहित प्राप्त हुआ है और 2.36 लाख मी. टन शीघ्र प्राप्त होगा। डीएपी का अक्टूबर 2022 के लिए आवंटन 4 लाख मी. टन है, जिसके विरूद्ध 2.65 लाख मी. टन ट्रांजिट सहित प्राप्त हुआ है। अक्टूबर, 2022 के कोटे की शेष यूरिया की मात्रा 2.36 लाख मी. टन और डीएपी की शेष मात्रा 1.35 लाख मी. टन मिलाकर माह नवम्बर 2022 के लिए यूरिया का आवंटन 9.36 लाख मी. टन, डीएपी 3.29 लाख मी. टन का संशोधित आवंटन आदेश माह नवम्बर 2022 के लिए जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही एडवांस प्लानिंग में माह दिसम्बर के लिए यूरिया की माँग 5 लाख मी. टन, डीएपी 1.25 लाख मी. टन, एनपीके 0.30 लाख मी. टन का अनुमान लगाया गया है। इसकी व्यवस्था के लिए भी प्रयास अभी से किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में होगा शासकीय उचित मूल्य दुकान पर वितरण : खाद्य मंत्री श्री सिंह

स्थानीय 888 युवाओं को वाहन के लिये 11.10 करोड़ का अनुदान

भोपाल : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता और बिचौलिए-ठेकेदारों पर अंकुश लगाने के लिये "मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना" को मंत्रि-परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में स्थानीय युवाओं को केन्द्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिये शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध करा कर वाहन उपलब्ध कराये जायेंगे। शासन द्वारा प्रति वाहन 1.25 लाख रूपये के अनुदान के मान से 888 वाहनों पर 11 करोड़ 10 लाख रूपये अनुदान के रूप में भुगतान किये जायेंगे।

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि प्रदाय केन्द्रों से राशन परिवहन कर उचित मूल्य दुकान तक पहुँचाने के लिये स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिये 7.5 मीट्रिक टन क्षमता के अधिकतम 25 लाख रूपये कीमत का

वाहन दिलवाया जायेगा। इससे अधिक राशि का वाहन क्रय करने पर हितग्राही को शेष राशि का भुगतान करना होगा। कीमत के 10 प्रतिशत डाउन पेमेंट के लिये 1.25 लाख रूपये राज्य शासन द्वारा और 1.25 लाख रूपये हितग्राही द्वारा भुगतान किये जायेंगे।

अतिरिक्त समय में हितग्राही कर सकेंगे वाहन का निजी उपयोग

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि 3 हजार क्विंटल सामग्री का प्रतिमाह 4 हजार किलोमीटर के मान से प्रति वाहन परिवहन अनुमानित है। वाहन मालिक प्रतिमाह 15 से 20 कार्य दिवस के अलावा शेष दिनों में वाहन का निजी उपयोग कर सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने बताया कि विगत रबी एवं खरीफ में 46 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के परिवहन पर 235.98 करोड़ का भुगतान किया गया।

जीपीएस से होगी वाहनों की निगरानी

खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि वाहनों में जीपीएस सुविधा रहेगी। सेंट्रल कमाण्ड कंट्रोल-रूम से वाहनों के मूवमेंट पर वाहनों की सतत निगरानी की जायेगी। वाहनों पर माइक सिस्टम के साथ शासन की योजनाओं का प्रदर्शन भी किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हितग्राही आयशर, इसूजु, महिन्द्रा, टाटा एवं अशोका लीलेंड कम्पनी के चिन्हित वाहनों में से अपनी पसंद का वाहन क्रय कर सकेंगे।

हितग्राही की पात्रता

हितग्राही संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी हो, उसकी उम्र 18 से 45 वर्ष हो और आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो। हितग्राही की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रूपये, हेवी मोटर व्हीकल संचालन का स्थाई लायसेंस, बैंक से डिफाल्टर न हो।

सेवानिवृत्त सैनिक भी पात्र होंगे, परंतु शासकीय सेवक और पेंशनर पात्र नहीं होंगे। हितग्राही अन्य स्व-रोजगार योजना से लाभान्वित न हो एवं आपराधिक प्रवृत्ति एवं पृष्ठभूमि के हितग्राही इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

तेंदूपत्ता संग्राहकों के बैंक खातों में अंतरित किये 41 करोड़ 63 लाख 29 हजार रुपये

- मध्यप्रदेश की धरती पर 15 नवम्बर से लागू होगा पेसा एक्ट : मुख्यमंत्री श्री चौहान
- 731 करोड़ रूपये की खालवा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि-पूजन और विभिन्न निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण
- अगले शिक्षण-सत्र से खालवा में शुरू होगा महाविद्यालय

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 15 नवम्बर से प्रदेश में पेसा एक्ट लागू कर दिया जायेगा, जिससे हमारे जनजातीय भाई-बहनों को कई सुविधाएँ मिलेंगी। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय भी मिलेगा। तेंदूपत्ता संग्राहक के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार देगी। अब तेंदूपत्ता के कुल लाभांश की 75 प्रतिशत राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों में वितरित की जायेगी। खालवा में अगले शिक्षण-सत्र से महाविद्यालय खोला जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज खालवा जिला खण्डवा में लघु वनोपज सहकारी समितियों की क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण सह जागरूकता एवं तेन्दूपत्ता लाभांश वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 786 करोड़ रूपये लागत के 43 कार्यों का भूमि-पूजन एवं 79 करोड़ 59 लाख रूपये लागत के 9 कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही खण्डवा, नर्मदापुरम, बैतूल एवं उज्जैन वृत्त के कुल 10 वन मण्डल की 102 लघु वनोपज समितियों के 1 लाख 68 हजार 601 संग्राहकों के बैंक खाते में 41 करोड़ 63 लाख 29 हजार 75 रूपये हस्तांतरित किये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि क्षेत्र के विकास में हर संभव प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि अपने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम स्थल पर लगी विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

हितग्राही हुए लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देवास के श्री चंदर पिता सहादर, कश्मिर पिता हजारी जिला खण्डवा, दयाराम पिता गुलाब बड़वाह, प्रेमदास पिता हरिराम नर्मदापुरम, राधेलाल यादव बैतूल को तेंदूपत्ता संग्रहण बोनस राशि के चेक देकर सम्मानित किया। साथ ही उद्यम कृषि योजना, "एक जिला-एक उत्पाद", आजीविका स्व-सहायता समूह, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, वन अधिकार पट्टा आदि योजनाओं में हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गांधी मेडिकल कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र श्री सुनील पिता शोभाराम इस्के एवं जबलपुर मेडिकल कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा सुश्री जानकी पिता कैलाश वास्कले को 50-50 हजार रूपये के चेक भेंट किया।

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को मुख्यमंत्री श्री चौहान से रू-ब-रू कराया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्ति योजना से लाभान्वित हो रहे है। उन्होंने बताया कि 731 करोड़ रूपये की एनव्हीडीए खालवा उद्वहन सिंचाई योजना से जिले के 76 गाँवों के निवासियों की जमीन सिंचित होगी। इसमें इंदिरा सागर जलाशय हरसूद तहसील के ग्राम नंदगाँव से जल उद्वहन कर खालवा तहसील लाया जायेगा।

खण्डवा जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, बैतूल सांसद श्री डी.डी. उईके, विधायक श्री देवेन्द्र वर्मा, श्री राम दांगोरे, श्री नारायण पटेल और श्री संजय शाह सहित जन-प्रतिनिधि, संभागायुक्त इंदौर श्री पवन शर्मा, कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह , पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

किसानों के सशक्तिकरण के लिये संकल्पित शिव-राज

भोपाल : धरती पुत्र शिवराज सिंह चौहान ने जबसे प्रदेश की कमान सम्हाली है, तभी से स्वर्णिम मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने में हर पल गुजरा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कहते हैं कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास में किसान की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसी सोच के मद्देनजर किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये निरंतर कार्य किये हैं, जो आज भी बदस्तूर जारी हैं। अपनी स्थापना के 67वें वर्ष में मध्यप्रदेश कृषि के क्षेत्र में अग्रणी प्रदेश है, जिसने कई कीर्तिमान रचते हुए लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त किया है।

प्रदेश आज विकसित राज्यों की दौड़ में शामिल है। गेहूँ उत्पादन के साथ ही उपार्जन में भी हम अव्वल हैं। हमने पंजाब जैसे राज्यों को पीछे कर बता भी दिया है और जता भी दिया है कि प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ परिश्रम की पराकाष्ठा करने को दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। गुणवत्ता में भी हम सबसे मुकाबला करने को तत्पर हैं। राज्य सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाएँ, कुशल और सक्षम नेतृत्व, वैज्ञानिकों के साथ ही किसानों की मेहनत का सुफल है कि प्रदेश की रायसेन मण्डी में धान समर्थन मूल्य से 1200 रूपये अधिक तक बिक रहा है। सरकार सतत प्रयास कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का दोगुना से ज्यादा लाभ मिले।

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से जनता को लाभान्वित करने में मध्यप्रदेश प्रथम पयदान पर है। उक्त योजना का लाभ देश में सबसे पहले हरदा जिले के किसान रामभरोस विश्वकर्मा को मिला। प्रदेश कृषि अधो-संरचना निधि के उपयोग में भी देश में अव्वल है। प्रदेश में इस निधि से 1508 प्रकरण में 852 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है, जो देश में अब तक किये गये व्यय की कुल 45 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 2-2 हजार रूपये की दो किश्तें प्रदान की जा रही हैं। अब तक प्रदेश के 80 लाख किसानों को 4751 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सबसे अधिक किसानों को लाभान्वित करने वाला राज्य है। योजना में रबी 2020-21 में ही 49 लाख किसानों को 7618 करोड़ रूपये की दावा राशि का भुगतान किया गया।

सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को लाभान्वित करने के लिये वन ग्रामों को भी योजना में शामिल करना, फसल अधिसूचित करने के लिये न्यूनतम सीमा 100 के स्थान पर 50 हेक्टेयर करना, क्षति आकलन के लिये बीमा पोर्टल को लेण्ड रिकॉर्ड के एनआईसी पोर्टल से लिंक करना, अवकाश के दिनों में भी बैंक खुलवा कर किसानों का बीमा कराना और बीमा कव्हरेज के स्केल ऑफ फायनेंस को 100 प्रतिशत तक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किये।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सिंचाई सुविधाओं में अकल्पनीय विस्तार हुआ है। आज प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का रकबा लगभग 45 लाख हेक्टेयर तक पहुँच चुका है। वर्ष 2025 तक इसे बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। प्रदेश जैविक खेती में पहले स्थान पर है। गुड गवर्नेंस इण्डेक्स 2021 में कृषि संबद्ध क्षेत्र में मध्यप्रदेश नम्बर वन है। कृषि विकास के लिये प्रदेश में ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक पर काम हो रहा है। इसके लिये कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं उन्नत तकनीकों के प्रयोग के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया (एकार्डा) की मदद ली जा रही है। एम-पोर्टल से एसएमएस द्वारा कृषि संबंधी सलाह किसानों को दी जा रही है। प्रदेश में बीज, उर्वरक, कीटनाशक लायसेंस प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है। प्रदेश में किसानों के हित में निर्णय लिया जाकर अब गेहूँ के साथ ही मूंग, चना, उड़द और मसूर जैसी दलहन और सोया, सरसों जैसी तिलहन का भी उपार्जन किया जा रहा है। सरकार किसानों से ग्रीष्मकालीन मूंग का उपार्जन भी कर रही है। इन सबसे किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग खुला है। सरकार ने फसलों के आने के साथ ही उपार्जन से किसानों को उपज का वाज़िब दाम मिलना सुनिश्चित किया है। किसान आधुनिक तकनीक से लैस हो रहे हैं।

प्रदेश में ग्रीष्मकालीन फसलों के लिये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के अतिरिक्त प्रयास किये जा रहे हैं। इसकी बदौलत ग्रीष्मकालीन फसलों के रकबे में 3 गुना तक की वृद्धि हुई है। आज ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल का रकबा बढ़ कर 7 लाख हेक्टेयर हो गया है। प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये प्राकृतिक कृषि बोर्ड गठित किया गया है। प्रदेश के दोनों कृषि विश्वविद्यालयों में जैविक/प्राकृतिक कृषि शाखाएँ प्रारंभ की गई हैं। किसानों को फसल तकनीकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिये कृषि विज्ञान केन्द्र में कृषि ओपीडी की स्थापना की गई है, जहाँ से कृषक व्हाटसअप और आईटी से कृषि वैज्ञानिकों से सम्पर्क कर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। सरकार ने किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिये किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केन्द्र (दूरभाष क्रमांक 0755-2558823) की स्थापना भी की है।

किसान अन्नदाता के साथ अब ऊर्जादाता भी बनेगा - केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी

प्रदेश सरकार सड़कों का जाल बिछाने के लिए लगातार प्रयासरत - मुख्यमंत्री श्री चौहान

भोपाल : केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को निरंतर कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अब मध्यप्रदेश कृषि उत्पादों का निर्यात भी करने लगा है। किसान अन्नदाता के साथ अब ऊर्जादाता भी बनेगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने मंडला में मंडला और डिंडोरी जिले के लिए 1261 करोड़ रूपये लागत की 5 सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि मंडला में प्रकृति का निवास है, यह रानी दुर्गावती की भूमि है तथा यहाँ कान्हा जैसा विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। जनजातीय कार्यों के विकास के लिए सड़कें अत्यंत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते सहित स्थानीय जन-प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सड़क विकास के प्रस्तावों पर विस्तृत अध्ययन कर योजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी।

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने देशभर में ऊर्जा के क्षेत्र में परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई नई परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मध्यप्रदेश में परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि मंडला, डिंडौरी एवं अन्य जनजातीय क्षेत्रों में बाँस के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है। बाँस से भविष्य में इथेनॉल का निर्माण होगा, जिससे परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों के लिए ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कान्हा-बालाघाट क्षेत्र में सड़क विकास के लिए नए प्रोजेक्ट को 'गति शक्ति योजना' में शामिल करने की बात कही।

मंडला-जबलपुर हाई-वे का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने के निर्देश

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी ने मंडला-जबलपुर हाई-वे के बारे में चर्चा की। उन्होंने हाई-वे निर्माण में गुणवत्ता से असंतुष्टि जाहिर की और मंडला एवं आसपास के क्षेत्र की जनता को सड़क से हुई परेशानी के लिए मंच से माफी मांगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के पुराने कार्य को रिपेयर करें तथा सड़क के खराब हिस्से के निर्माण के लिए जल्द नया टेंडर जारी करें। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने आगामी वर्षों में अलग-अलग परियोजनाओं से सड़क एवं पुलों के विकास के बारे में चर्चा की।

नर्मदा एक्सप्रेस-वे पर अध्ययन जारी

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा देश के सभी धार्मिक स्थानों तक पहुँचने के लिए लगातार बारह-मासी सड़कों का निर्माण जारी है। उन्होंने अमरकंटक से लेकर धार-झाबुआ तक नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के संबंध में कहा कि इस मार्ग के निर्माण के लिए मंत्रालय द्वारा अध्ययन जारी है। इस मार्ग के विकास से नर्मदा प्रदक्षिणा करने वाले श्रद्धालुओं को निश्चित रूप से लाभ होगा। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मध्यप्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी भाषा में भी प्रारंभ करने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सभी विद्यार्थियों की ओर से शुभकामनाएँ दी। उन्होंने कहा कि गरीब एवं वंचित वर्गों तक विकास को पहुँचाना हमारा संकल्प है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार चारों तरफ सड़कों के जाल बिछाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने मंडला और डिंडोरी जिले के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई नई 5 सड़क परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि वर्ष 2003 के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 3 लाख किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा उद्गम से लेकर धार-झाबुआ तक 'नर्मदा एक्सप्रेस-वे' बनाने का प्रस्ताव है। 'नर्मदा एक्सप्रेस-वे' के दोनों ओर औद्योगिक क्षेत्र के विकास का प्रयास किया जाएगा, जहाँ स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योग लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार विकास के कार्यों में कमी नहीं होने देगी। उन्होंने मंडला-डिंडौरी क्षेत्र में घर-घर पानी पहुँचाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने सीएम जनसेवा अभियान में मंडला जिले में प्राप्त तथा स्वीकृत आवेदनों की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल एक लाख 84 हजार 753 आवेदन में से एक लाख 56 हजार 944 को स्वीकृत किया जा चुका है। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी से कान्हा क्षेत्र को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ने तथा नर्मदा सौन्दर्यीकरण और विकास के लिए नए प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने मंडला जिले में नए सीएम राईज स्कूलों के संचालन, विशेष कोचिंग के माध्यम से नीट परीक्षा में जनजाति बहुल जिलों के विद्यार्थियों की सफलता तथा मध्यप्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम में शुरू किए जाने की जानकारी दी।

15 नवंबर से लागू होगा 'पेसा एक्ट'

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 15 नवंबर को प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसमें प्रदेश में पंचायत से लेकर जिला स्तर तक समारोहपूर्वक अनेक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर से ही संपूर्ण प्रदेश में सामाजिक समरसता के साथ 'पेसा एक्ट' भी लागू किया जाएगा। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के भूमि-पूजन के लिए जल्द मंडला आने की बात भी कही।

सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास महाकौशल क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव का पल

केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि पाँच सड़क परियोजना का शिलान्यास महाकौशल क्षेत्र के लिए अत्यंत गौरव का पल है। उन्होंने सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी का मंडला एवं डिंडोरी की जनता तथा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों की ओर से अभिनंदन किया। श्री कुलस्ते ने जबलपुर-नैनपुर बाईपास, कान्हा क्षेत्र को प्रमुख मार्गों से जोड़ने, नैनपुर-सिवनी हाई-वे, मंडला-लखनादौन के लिए नई परियोजनाओं की स्वीकृति का आग्रह किया।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी विजनरी, दृष्टिवान तथा नवाचार के धनी

प्रदेश के लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी को नई सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने वर्ष 2014 के बाद से मध्यप्रदेश में सड़क एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी दी। मंत्री श्री भार्गव ने सड़क, पुलिया एवं फ्लाईओवर निर्माण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी को विजनरी, दृष्टिवान एवं नवाचार का धनी बताया।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी तथा मुख्यमंत्री श्री चौहान का स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने कलगी-साफा पहना कर स्वागत किया। कार्यक्रम में 5 सड़क परियोजना पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। अतिथियों ने सड़क परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद सुश्री संपतिया उईके, विधायकगण सर्वश्री देवसिंह सैयाम, डॉ. अशोक मर्सकोले और श्री नारायण पट्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय कुशराम, नगरपालिका अध्यक्ष श्री विनोद कछवाहा और जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कमलेश टेकाम उपस्थित रहे।

सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी खाद संबंधी समस्याओं का करें समाधान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक बुला कर दी हिदायत

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सभी जिलों में किसानों के लिए पर्याप्त खाद की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस बारे में पहले भी निर्देश दिए गए हैं। फिर भी कहीं कहीं से प्राप्त हो रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाए। आज पन्ना भ्रमण में भी मुख्यमंत्री श्री चौहान को कुछ वितरण केंद्रों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, जिसे लेकर उन्होंने अप्रसन्नता व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध और समाधान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज पन्ना जिले के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री निवास में सहकारिता मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया के साथ प्रमुख सचिव सहकारिता, आयुक्त सहकारिता और प्रबंध संचालक मार्कफेड के साथ प्रदेश में खाद व्यवस्था के बारे में चर्चा कर व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरस्त रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खाद की उपलब्धता के साथ सुचारू वितरण व्यवस्था के निर्देश दिए।

ग्रामीण विकास योजनाओं में मध्यप्रदेश "स्टार परफॉर्मर"

अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा

भोपाल : अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास और विकास आयुक्त श्री मलय श्रीवास्तव ने कहा है कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में मध्यप्रदेश "स्टार परफॉर्मर" है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण, ग्राम सड़क योजना, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन आदि के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। विभागीय अधिकारी पूरी तन्मयता, मेहनत और निष्ठा के साथ कार्य करते रहें और सभी योजनाओं में प्रदेश और बेहतर प्रदर्शन करें।

अपर मुख्य सचिव श्री श्रीवास्तव आज विकास आयुक्त कार्यालय, विंध्याचल भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण सुश्री तन्वी सुंद्रियाल और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण आजीविका मिशन श्री ललित मोहन बेलवाल उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री श्रीवास्तव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में सभी पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा में विभागीय योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित किये जाएँ। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रदेश को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए संबंधित अधिकारियों से निरंतर समन्वय कर केन्द्र सरकार से जितने संसाधन लाये जा सकें लाये जाएँ।

श्री श्रीवास्तव ने इसके पूर्व विकास आयुक्त कार्यालय का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कार्यालय भवन और कार्य-स्थल पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने को कहा।

"सिवनी जम्बो सीताफल" ब्रांड को देश-प्रदेश में लोकप्रिय बनाएँ : मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सिवनी में "एक जिला-एक उत्पाद" के उत्पाद सीताफल का किया अवलोकन

भोपाल : मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी में "एक जिला-एक उत्पाद" कार्यक्रम अंतर्गत उत्पाद "सिवनी जम्बो सीताफल" का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान सीताफल के जम्बो आकार, विशिष्ट गुण तथा स्वाद आदि के संबंध में अवगत हुए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने "सिवनी जम्बो सीताफल" को लोकप्रिय बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयास पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि "सिवनी जम्बो सीताफल" उत्पादक किसान और इसका प्र-संस्करण कर पल्प और अन्य उत्पाद बनाने वाली आजीविका मिशन की बहनों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य दिलाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ब्रांड की बेहतर मार्केटिंग कर देश- प्रदेश में इसे लोकप्रिय बनाने के भी निर्देश दिये।

सिवनी जिले में 656 हेक्टेयर क्षेत्र में 6500 मीट्रिक टन से अधिक सीताफल का उत्पादन होता है। सीताफल का वजन 600 से 700 ग्राम होने से इसका नाम "सिवनी जम्बो सीताफल" रखा गया है। अपने विशिष्ट आकार तथा स्वाद से इसकी देश-प्रदेश में अच्छी माँग है। इसे विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए आजीविका मिशन के महिला स्व-सहायता समूह की सहभागिता से सीताफल की पल्प यूनिट प्रारंभ की गई है और एफपीओ का गठन किया गया है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं प्रभारी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन, विधायक सर्वश्री दिनेश राय और राकेश पाल मौजूद थे।

हर किसान को मिलेगी पर्याप्त खाद : मंत्री श्री राजपूत

राजस्व एवं परिवहन मंत्री पहुँचे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में और सुनी समस्याएँ

भोपाल : राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि हर किसान को पर्याप्त खाद मिलेगी। खाद प्राप्ति में किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा हर सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई गई है। मंत्री श्री राजपूत सागर जिले के ग्राम सुरखी में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर में आम जनता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में मंत्री श्री राजपूत ने सागर जिले के ग्राम सुमडेरी, पड़ारसोई, बंसिया गंगे और जलंदर में ग्रामीणों की समस्याएँ सुनी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शिविर में आने वाले किसानों की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे सभी व्यक्तियों को शासकीय

योजनाओं का लाभ प्रदान करना है, जो अब तक वंचित रहे हैं। उन्हें लाभ देने के लिए सुरखी क्षेत्र में शिविर लगाये जा रहे हैं। ये शिविर 2 चरण में लगाये जा रहे हैं। प्रथम चरण में अधिकारी-कर्मचारी हितग्राहियों से उनकी समस्याओं के संबंध में आवेदन प्राप्त करेगें और दूसरे चरण में हितग्राहियों को समस्याओं के निराकरण से अवगत कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन शिविरों से हमारे क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण उनके गाँव में ही हो रहा है। हमारे क्षेत्र के लोग अपने कार्य के लिए अधिकारियों और कार्यालयों के चक्कर न लगाएँ। इस उद्देश्य को लेकर हर ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में पात्र व्यक्तियों को मिल रहा है योजना का लाभ

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि इन शिविरों में अधिकारियों का पूरा दल पहुँचता है और ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करता है। मंत्री श्री राजपूत ने मंच से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अंतर्गत अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिये कि लोगों की समस्याएँ गंभीरता से सुने और उन पर कार्रवाई करें। यह शिविर औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए है। अगर किसी भी अधिकारी-कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, अत: अपनी जिम्मेदारी को निभाए और लोगों की समस्याओं का हर हाल में निराकरण करें।

मंत्री श्री राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन लोगों को आवेदन बनाने में परेशानी हो रही है, उनकी समस्या सुन कर अधिकारी-कर्मचारी खुद आवेदन बनाएँ और समस्या का निराकरण करें।

सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हुआ

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 की दी जानकारी

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बुधवार को निर्वाचन सदन मध्यप्रदेश सभागार में 9 नवंबर से शुरू हुए मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 में होने वाली गतिविधियों के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सभी 64 हजार 100 मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। सभी जिला और तहसील स्तर पर मतदाता जागरूकता की गतिविधियाँ की गई। रैली और दौड़ के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। नवंबर माह में 4 दिन विशेष शिविर लगाए जाएंगे। शनिवार और रविवार को होने वाले विशेष शिविरों में बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों में आने वाले गाँवों में भ्रमण करेंगे। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा होगा, उनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा। बीएलओ एक माह तक कार्य-दिवस में सुबह से शाम तक मतदान केंद्रों में उपस्थित रहेंगे। 9 नंवबर से 8 दिसंबर तक दावा आपत्ति ली जाएगी और 26 दिसंबर तक प्राप्त हुए आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 5 जनवरी 2023 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीईओ श्री राजन ने कहा कि एक अक्टूबर 2023 की स्थिति में यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो रहा है तो वह नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन दे सकता है। जिस दिन वह 18 वर्ष का हो जाएगा उसका नाम जुड़ जाएगा। उसे दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।

1950 पर करें संपर्क

सीईओ श्री राजन ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी कार्य और समस्या के समाधान के लिए सीईओ एमपी इलेक्शन के टोल फ्री नंबर 1950 पर काल कर जानकारी ली जा सकती है।

ऑनलाइन-आफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीईओ श्री राजन ने कहा कि युवा मतदाता जिनकी उम्र 18 साल हो गई है और नाम नहीं जुड़ पाया है वे युवा वोटर हेल्पलाइन एप और एनवीएसी डॉट इन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आवेदक को फॉर्म भर कर बीएलओ को देना होगा।

(पृष्ठ 1 का शेष)

किसानों की आय को दोगुना करने....

उन्हें गाड़ी खरीदने के लिये बैंक से राज्य सरकार की गारंटी पर लोन दिलाया जायेगा। नौजवानों को 1 लाख 20 हजार रूपये किराया भी दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब महिलाओं को घर-घर टोटी लगा कर जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन से गाँव -गाँव में पाइप लाइन बिछा कर नल कनेक्शन दिये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरैना जिले में अमृत सरोवर का अच्छा कार्य हुआ है। इससे जल-संग्रहण के साथ भू-जल स्तर बढ़ेगा और सिंचाई एवं पशुओं को पेयजल की उपलब्धता होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुरैना के स्टेडियम का 10 करोड़ रूपये की लागत से उन्नयन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि ग्वालियर-चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए अनेक योजनाएँ शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय नहरों से पानी टेल एंड तक नहीं पहुँचता था। हमने नहरों को पक्का बना कर टेल एंड तक पानी पहुँचाया है। पहले मात्र साढ़े 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा था, उसे बढ़ा कर हमने 45 लाख हेक्टेयर कर दिया है। अब हमारा लक्ष्य इसे 65 लाख हेक्टेयर करने का है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी में होगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवा भी आसानी से डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गाँव के विकास और खेती को लाभकारी बनाने के लिये अनेक नवाचार कर रहे हैं। फसल बीमा सुरक्षा के साथ किसान सम्मान निधि से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मान्यता है कि किसान की माली हालत सुधरेगी तो देश की माली हालत भी बेहतर होगी। इस अवधारणा को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री चौहान पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश के हर गाँव और हर शहर का विकास हो रहा है। प्रदेश की कृषि विकास दर में बढ़ोत्तरी हुई है। किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। सिंचाई का क्षेत्र लगातार बढ़ने का लाभ भी सीधे किसानों को मिल रहा है।

श्री तोमर ने कहा कि किसानों के लिये यह सिर्फ सम्मेलन नहीं है। यहाँ लगातार तीन दिन किसानों को उन्नत खेती का प्रशिक्षण, नई तकनीक और बायो-फर्टिलाइजर का उपयोग, कम पानी में धान की उपज, दलहन, तिलहन और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने संबंधी 40 सत्र होंगे। किसानों की प्रशिक्षण क्लास भी लगेगी और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा उनके प्रश्नों का समाधान भी किया जायेगा।

लोकार्पण-शिलान्यास

कृषि मेले में मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर ने 101 अमृत सरोवर का लोकार्पण, मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक और स्पोर्टस कॉम्पलेक्स का शिलान्यास किया। साथ ही जिला चिकित्सालय मुरैना का नामकरण कुँअर जाहर सिंह शर्मा की शिला पट्टिका का अनावरण किया। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में "मेरी पॉलिसी मेरे हाथ" वितरित की गई। आजीविका मिशन के तहत दो महिला स्व-सहायता समूहों को ढ़ाई करोड़ रूपये के चेक भेंट किये। कृषि मेले में किसानों और खेती से संबंधित छोटे-बड़े उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है।

प्रदेश के उद्यानिकी प्र-संस्करण एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश कृषि उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है। प्रदेश लगातार पिछले 6 वर्षों से केन्द्र सरकार की ओर से कृषि के क्षेत्र में दिये जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त कर रहा है। प्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार नये-नये आयाम एवं नवाचार कर रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि रबी एवं खरीफ फसलों के साथ उद्यानिकी फसलें भी लें, जिससे खेती के साथ अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त हो सके।

केन्द्रीय कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा ने बताया कि कृषि मेला में किसानों के मार्गदर्शन के लिये प्रतिदिन कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर 12-12 अलग-अलग तथा 4-4 सामूहिक सत्र होंगे, जिनमें देश के कृषि विशेषज्ञ जानकारी एवं प्रेजेन्टेशन देंगे। किसानों को अद्यतन जानकारी देने के लिये प्रदर्शनी के 132 स्टॉल लगाये गये हैं। इनमें अनेक कृषि उन्नत उपकरण और पेस्टिसाइड्स प्रदर्शित किये गये हैं।

कार्यक्रम में अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष श्री रघुराज सिंह कंषाना, एमपी एग्रो के अध्यक्ष श्री ऐदल सिंह कंषाना, ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिर्राज डंडोतिया, सांसद श्री विवेक शेजवलकर, भिण्ड-दतिया संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती संध्या राय, विधायकगण, अन्य जन-प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में किसान बंधु उपस्थित थे।

भोपाल दुग्ध संघ को मिला ए+ ग्रेड

भोपाल : भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को विभिन्न मानकों के आधार पर 106 में से 101 अंक दिये गये हैं। प्रदेश के किसी भी दुग्ध संघ को पहली बार इतने अंक प्राप्त हुए हैं। भोपाल दुग्ध संघ को ऑडिट में ए+ ग्रेड प्राप्त हुआ है। दुग्ध संघ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर.पी.एस. तिवारी ने बताया कि पिछले वर्ष भी दुग्ध संघ को 96 अंकों के साथ ए+ ग्रेड मिला था। ए+ ग्रेड के लिए 95-106 अंक श्रेणी सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निर्धारित है।

मंत्री श्री पटेल ने दी बधाई

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने भोपाल दुग्ध संघ को लगातार भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा ए+ ग्रेड और ऑडिट में 5 अंक की उल्लेखनीय वृद्धि के लिए अधिकारी-कर्मचारियों को बधाई दी है। मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि प्रयास करें कि अगली बार दुग्ध संघ को पूरे 106 अंक प्राप्त हों। भोपाल दुग्ध संघ को यह अंक सभी आयामों में स्वच्छता, अनुभवी और तकनीकी ज्ञान से संपन्न स्टाफ, दूध और दुग्ध उत्पादों के बेहतर प्रबंधन, कोल्ड स्टोरेज का हर 2 घंटे में तापमान मापन, द्वार पर प्लास्टिक स्ट्रेप कर्टेन, डबल डोर स्लाडिंग आदि में प्राप्त हुए हैं।

(पृष्ठ 1 का शेष)

किसानों को खाद के लिए लाइन...

- 11 नवम्बर की स्थिति में यूरिया का स्टॉक 2.25 लाख मीट्रिक टन है। डीएपी का स्टॉक 1.45 लाख मीट्रिक टन एवं एनपीके का स्टॉक 1.11 लाख मीट्रिक टन है।
- विगत वर्ष 1 अप्रैल, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक विक्रय मात्रा के अनुसार 11 नवम्बर, 2022 तक यूरिया 13 जिलों (नर्मदापुरम कटनी, छतरपुर, रायसेन, सतना, जबलपुर, इंदोर, बेतूल, श्योपुर, रतलाम, नीमच, झाबुआ, अलिराजपुर) में, डीएपी 6 जिलों (बालाघाट, हरदा, टीकमगढ़, दमोह, निवाडी, अनुपपुर) में, एनपीके 17 जिलों (विदिशा, उज्जैन, नर्मदापुरम, सीहोर, सागर, भोपाल, खरगोन, नीमच, सिवनी, खण्डवा, शाजापुर, ग्वालियर दतिया देवास, आगरमालवा, बैतूल, इंदोर) में, डीएपी, एनपीके 04 जिलों (नर्मदापुरम, हरदा, शाजापुर, निवाडी) में भण्डारण कम है, जिनकी शीघ्र पूर्ति की जा रही है।
- विपणन संघ द्वारा माह नवम्बर के लिए 175 यूरिया की रेक एवं 78 रेक डीएपी की मांग की गई है, जिसके विरूद्ध 1 नवम्बर से 11 नवम्बर तक 57 यूरिया की रेक एवं 36 डीएपी की रेक एवं एनपीके की 15 रेक ट्रांजिट सहित प्राप्त है।
- विपणन संघ के 240 डबललॉक केन्द्रों से नगद वितरण प्रारंभ है, भीड़ वाले डबललॉक केन्द्रों पर 150 अतिरिक्त केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से 144 केन्द्रों द्वारा विक्रय किया जा रहा है।
- जिलों को डबललॉक केन्द्रों पर निजी उर्वरक विक्रेताओं के काउंटर स्थापित करने के निर्देश 3 नवम्बर, 2022 को जारी किये गये। 4 नवम्बर को 23 काउंटर प्रारंभ किये गये थे, जो बढ़ कर 10 नवम्बर को 406 काउंटर हो गये हैं।

नवंबर माह में करें इन 5 फसलों की खेती

देश में खरीफ की प्रमुख फसल धान की कटाई का काम अपने अंतिम चरण में हैं। किसान खरीफ की फसलों की कटाई का काम पूरा करके रबी फसलों की बुवाई की तैयारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है सही फसल का चुनाव करना। किसान रबी सीजन में कौन सी फसल की बुवाई करें जिससे फसल का सही उत्पादन प्राप्त हो और किसान बेहतर मुनाफा प्राप्त कर सके।

भारत में बोई जाने वाली रबी सीजन की प्रमुख फसलें

रबी की फसल भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती है जो कम तापमान में बोई जाती है, फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। आलू, मसूर, गेहूं, जौ, तोरिया (लाही), मसूर, चना, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं। वहीं बात करें रबी सीजन की प्रमुख सब्जी फसलों की तो इसमें टमाटर, बैगन, भिन्डी, आलू, तोरई, लौकी, करेला, सेम, फूलगोभी, पत्ता-गोभी, गाठ-गोभी, मूली, गाजर, शलजम, मटर, चुकंदर, पालक, मेंथी, प्याज, आलू, शकरकंद आदि सब्जियां उगाई जाती हैं।

नवंबर माह में करें इन फसलों की बुवाई

नवंबर महीना में समान्यत: रबी सीजन की फसलों व सब्जियों की बुवाई होती हैं, नवंबर माह में प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसलें निम्नलिखित हैं-

1. गेहूं

गेहूं भारत में रबी सीजन में बोई जाने वाली एक मुख्य फसल है। गेहूं का उपयोग मनुष्य अपने जीवनयापन हेतु मुख्यत रोटी के रूप में करते हैं, गेहूं में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, एवं हरियाणा गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गेहूं की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं। वो बाते निम्नलिखित हैं

- गेहूं की बुवाई का उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से नवंबर तक का हैं।
- गेहूं की फसल में बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों के बीज का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं की करण नरेन्द्र, करण वंदना, पूसा यशस्वी, करण श्रिया और डीडीडब्ल्यू 47 आदि उन्नत किस्में हैं।
- गेहूं की बुआई करते समय कम तापमान और फसल के पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की जरूरत होती हैं।
- गेहूं की खेती करते समय अच्छे फसल उत्पादन के लिए मटियार दोमट भूमि को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 8 तक का होना चाहिए।
- गेहूं की खेती करते समय बीज की बुआई से पहले बीज की अंकुरण क्षमता की जांच ज़रूर करनी चाहिए अगर गेहूं का बीज उपचारित नहीं है तो बुआई से पहले बीज को किसी फफूंदी नाशक दवा से उपचार अवश्य करना चाहिए।
- गेहूं की फसल में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सही मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए।
- गेहूं की फसल बुवाई के 20 से 25 दिन के बाद पहली सिंचाई करना चाहिए। गेहूं की फसल में 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती हैं।
- फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय-समय पर निराई-गुड़ाई करना आवश्यक होता हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप रसायन का भी छिड़काव कर सकते हैं।

2. चना

चना रबी सीजन की महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चना के 100 ग्राम दाने में औसतन 11 ग्राम पानी, 21.1 ग्राम प्रोटीन, 4.5 ग्राम वसा, 61.65 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 149 मि.ग्रा. कैल्शियम, 7.2 मिलीग्राम लोहा, 0.14 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन तथा 2.3 मिलीग्राम नियासिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते है। हमारे देश में चना की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा बिहार है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में चना की खेती की जाती है व देश में चना का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही है। चना की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं। वो बाते निम्नलिखित हैं

- चना की बुवाई करने के लिए मध्य अक्तूबर से नवंबर महीना सबसे उपयुक्त होता हैं।
- चना की खेती करने के लिए मध्यम वर्षा (60-90 सेटीमीटर वार्षिक वर्षा) और सर्दी वाले क्षेत्र सबसे उपयुक्त है।
- चना की खेती करने के लिए दोमट व मटियारा मिट्टी में सफलता पूर्वक किया जा सकता है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 तक का उपयुक्त रहता है।
- चना की खेती करने के लिए कम और ज्यादा तापमान दोनों ही फसल के लिए हानिकारक है। चना की बुवाई गहरी काली और मध्यम मिट्टी में करें।
- चना की खेती करते समय अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों की बीजों की ही बुवाई करें। चना की पूसा-256, केडब्लूआर-108, डीसीपी 92-3, केडीजी-1168, जेपी-14, जीएनजी-1581, गुजरात चना-4, के-850, आधार (आरएसजी-936), डब्लूसीजी-1 और डब्लूसीजी-2 आदि प्रमुख उन्नत किस्में हैं।खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 30 से 35 दिन बाद निराई-गुड़ाई अवश्य करना चाहिए।
- चना की फसल में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सही मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिए।
- चना के खेत में पानी का जमाव ना होने दे, अगर पानी जमा हो रहा हो तो उचित जल निकास की व्यवस्था करें।
- कीड़ों व रोगों से फसल के बचाव हेतु समय-समय पर रासायनिक छिड़काव अवश्य करें।

3. सरसों

सरसों रबी सीजन की मुख्य तिलहनी फसल हैं। सरसों की खेती भारत के सभी स्थानों पर की जाती है। मुख्य रूप् से सरसों की खेती हरियाणा, राजस्थान, मध्यकप्रदेश, उत्तकर प्रदेश और महाराष्ट्रक में की जाती है। सरसों की खेती की खास बात यह है की यह सिंचित और असिंचित, दोनों ही तरह के खेतों में उगाई जा सकती है। सोयाबीन और पाम के तेल के बाद विश्व में यह तीसरी सब से ज्यादा महत्तवपूर्ण तिलहन फसल है। मुख्य तौर पर सरसों के तेल के साथ-साथ सरसों के पत्ते का उपयोग सब्जी बनाने में होता हैं और सरसों की खली भी बनती है जो कि दुधारू पशुओं को खिलाने के काम आती है। सरसों की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं। वो बाते निम्नलिखित हैं

- सरसों की खेती करने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेट तापमान होना चाहिए, सरसों की खेती करने के लिए दोमट भूमि सर्वोतम होती है।
- सरसों की खेती करने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए
- सरसों की उन्नत किस्मों में पूसा बोल्ड, क्रान्ति, पूसा जयकिसान (बायो 902), पूसा विजय आदि हैं।
- सरसों की बुवाई करते समय उन्नत किस्मों के बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए
- सरसों की फसल में पहली सिंचाई 25 से 30 दिन के बाद करना चाहिए। इसकी खेती में 2 से 3 सिंचाई करना आवश्यक होता हैं। ध्यान रहें सरसों की फसल में फलियों में दाना भरने की अवस्था में सिंचाई नहीं करना चाहिए। फलियों में दाना भरने की अवस्था में सिंचाई करने से फसल उत्पादन प्रभावित होता हैं।
- सरसों की खेती करते समय अधिक मात्रा में उपज प्राप्त करने के लिए खाद व उर्वरक का सही मात्रा में प्रयोग करना आवश्यक होता हैं।
- सरसों की खेती करते समय खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई-गुड़ाई करना आवश्यक होता हैं।

4. आलू

आलू का भारत में पैदा होने वाली सब्जियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसीलिए आलू को सब्जियों का राजा कहां जाता हैं। आलू में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। आलू की खेती वैसे तो सभी क्षेत्रों में होती हैं लेकिन भारत में आलू की खेती सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में होती है। आलू की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं। वो बाते निम्नलिखित हैं

- आलू की बुवाई करने का उपयुक्त समय अक्तूबर से नवंबर का हैं
- आलू की खेती करने के लिए समतल और मध्यम ऊंचाई वाले खेत ज्यादा उपयुक्त होते हैं। साथ ही अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी जिसकी पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच का होना चाहिए।
- आलू की फसल में सबसे पहले कल्टीवेटर की मदद से 2 से 3 बार खेत की जुताई करें। खेत की जुताई करने के बाद पाटा जरूर लगाए ताकि मिट्टी भुरभूरी और खेत समतल हो जाए। पाटा लगाने से आलू के कंदो के विकास में आसानी होती है।
- आलू की खेती में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों की बीजों का चयन करना चाहिए। आलू की उन्नत किस्मों में राजेन्द्र आलू, कुफरी कंच और कुफरी चिप्ससोना आदि मुख्य है।
- आलू की बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखे।
- आलू की खेती करते समय 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण करने के लिए निराई-गुड़ाई अवश्य करें और निराई के दौरान आलू पर मिट्टी चढ़ाकर नालियों को व्यवस्थित करें जिससे आलू के पौधे का विकास सही तरीके से होता हैं।
- आलू की खेती में कम पानी की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई आलू की फसल की बुवाई के 10 से 20 दिनों के अंदर कर देनी चाहिए। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल में थोड़ी-थोड़ी सिंचाई करते रहने चाहिए।
- आलू के खेत की सिंचाई करते समय इस बात का ख्याल रखें कि मेड़ 2 से 3 इंच से ज्यादा नहीं डूबे।

5. मटर

भारत में रबी फसलों में मटर का महत्वपूर्ण स्थान है। मटर का इस्तेमाल सब्जी व दाल के रुप में होता हैं। मटर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, और विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मटर एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग कई प्रकार की सब्जियों के साथ किया जाता है। भारत में मटर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश हैं। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में भी मटर की खेती की जाती हैं। मटर की फसल में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता हैं। वो बाते निम्नलिखित हैं

- मटर की खेती करने के लिए उपयुक्त समय मध्य अक्टूबर से नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त होता हैं
- मटर की खेती करते समय मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए
- मटर की खेती में अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों की बीजों का ही प्रयोग करें मटर की आर्केल, लिंकन, बोनविले, मालवीय मटर,पंजाब 89, पूसा प्रभात, पंत 157 आदि प्रमुख उन्नत किस्में हैं।
- मटर की बुवाई में खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 बार कल्टीवेटर की मदद से जुताई करें व भूमि को समतल करने के लिए पाटा अवश्य लगायें।
- मटर की बुवाई करने के लिए देशी हल जिसमें पोरा लगा हो या सीड ड्रिल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। बीज की गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।
- मटर की खेती में 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी सिंचाई फसल में फलियां बनने के समय करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हल्की सिंचाई करें और खेत में पानी जमा ना होने दे इसके लिए खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था अवश्य करें।
- मटर की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय-समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें। जरुरत पड़ने पर खरपतवार नियंत्रण के लिए आप रसायन का भी छिड़काव कर सकते हैं।

किसान, उपज विक्रय के समय कृषि मंडी में आधार, समग्र आईडी आदि दस्तावेज लाए

भोपाल : जिले के समस्त किसान भाईयो से अपील की गई है कषि उपज मंडियों में उपज विक्रय हेतु लाते समय उक्तानुसार आधार कार्ड, किसान पंजीयन, समग्र आईडी आदि दस्तावेज साथ में लायें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। किसान का नाम, मोबाईल नम्बर समग्र आईडी या आधार नम्बर, किसान पंजीयन कोड दर्ज करने पर किसान द्वारा मण्डी में विकय की गई मात्रा की जानकारी देखी जा सकेगी उसका प्रिन्ट निकाल कर केन्द्र पर नियोजित नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण कर केन्द्र प्रभारी को दी जायेगी, तद्नुसार किसान की पात्रता की शेष मात्रा का गेहूँ का नियमानुसार उपार्जन, खरीदी की जायेगी।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किसानो के पंजीयन का दुरुपयोग रोकने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं । अब उपार्जन मण्डी मिलान प्रणाली अंतर्गत मण्डी में की गई एन्ट्री की जानकारी जिले के समस्त निर्धारित केन्द्रों पर उपार्जन मण्डी मिलान प्रणाली समिति के विकल्प पर रियलटाईम किसानवार जानकारी प्रदर्शित होगी।

सहकारी समितियों का पंजीयन केवल ऑनलाइन

सीहोर : जिले में सहकारी समितियों का पंजीयन अब केवल ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से समितियों का पंजीयन करवाने के लिए संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि समितियों के पंजीयन के लिए विभागीय ऑनलाईन पोर्टल http:icmis.mp.gov.in पर जाकर 21 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं।

पोर्टल पर नवीन संस्था का आवेदन करने के लिए आवेदक उल्लेखित लिंक पर जाकर स्वयं एमपी ऑनलाईन नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदक को पोर्टल पर अपना लॉग इन क्रिएट करना होगा। लॉग इन क्रिएट करने के लिए आधार से लिंक मोबाईल नंबर प्रविष्टि कर ओटीपी सत्यापन होगा। प्रस्तावित संस्था की जानकारी एवं प्रथम आवेदन की जानकारी भरकर पासवर्ड निर्मित करेगा। तत्पश्चात आवेदक का लॉगिन निर्मित हो जायेगा। अंशपूंजी का मूल्य दर्ज करके प्रस्तावित सदस्यों के फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर तदर्थ कमेटी नामांकित कर दस्तावेज अपलोड कर अंशों का मूल्य एवं सदस्यता प्रवेश शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करेगा। आधार नंबर से वर्चुएल आईडी जनरेट होगा और आवेदक का ई-साईन कर आवेदन ऑनलाईन जमा करना होगा।

विभाग द्वारा आवेदन प्राप्त होने पर अधिकतम 45 दिवस के भीतर आवेदन पर कार्यवाही की जायेगी। कुछ कमियां होने पर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। जिसकी सूचना एसएमएस से दी जायेगी। पंजीयन पोर्टल पर आवेदन मान्य होने पर पोर्टल से ही पंजीयन प्रमाण-पत्र जनरेट होगा जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर रहेंगे।

नागरिक जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ प्राप्त करें

सीहोर : मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दौरान केन्द्र एवं राज्य शासन की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों से इन योजनाओं का लाभ लेने का आग्रह किया गया है।इसी क्रम में बैंक एवं संस्थागत वित्त द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना संचालित की जा रही है। योजना का लाभ बैंक खाताधारक 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के उन सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने इस योजना में शामिल होने तथा ऑटो- डेबिट के लिए अपनी सहमति दी हो। योजना में दो लाख रूपये का जीवन कवर एक जून से 31 मई तक की एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में दो लाख रूपये का जोखिम कवरेज है। इसका प्रीमियम 436 रूपये प्रति वर्ष है, जो अभिदाता द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार योजना के अंतर्गत प्रत्येक वार्षिक कवरेज के लिए 31 मई या उससे पूर्व उनके बैंक खाते से एक किश्त में ऑटो- डेबिट किया जाता है। इस योजना का प्रस्ताव जीवन बीमा निगम तथा अन्य जीवन बीमाकर्ता, जो इस प्रयोजन से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्ति करके बैंकों से समझौता करके इन्हीं शर्तों पर इस उत्पाद का प्रस्ताव करने के लिए इच्छुक हो, द्वारा किया जाता है।

दस वर्ष से अधिक पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराएं

सीहोर : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा दस वर्ष पुराने आधार कार्ड को अपडेट करने का निर्णय लिया गया है। आधार कार्ड ने नागरिक के पहचान-पत्र के रूप में विश्वसनीयता हासिल की है। आधार कार्ड का उपयोग आज आम नागरिक द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। शासन के इस निर्णय से ऐसे आधारकार्डधारी, जिन्होंने पिछले 10 वर्ष में आधार कार्ड कभी भी अपडेट नहीं कराया है, उन्हें अपने आधार कार्ड अपडेट कराना होंगे।आधार कार्ड के अपडेट कराने से जिन नागरिकों के कार्ड पुराने और अस्पष्ट हो गए हैं, वे नये कार्ड बनवा सकेंगे। इससे आधार प्रमाणीकरण

एवं सत्यापन में होने वाली असुविधा से बचा जा सकेगा।

ऐसे व्यक्ति , जिन्होंने अपना आधार कार्ड 10 वर्ष पूर्व बनवाया था और इसके बाद कभी अपडेट नहीं करवाया है, ऐसे आधार नम्बर धारकों से डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने का आग्रह किया गया है।इस संबंध में आधार नम्बर धारकों को UIDAI ने डॉक्यूमेंट अपडेट की सुविधा निर्धारित शुल्क के साथ प्रदान की है। आधार नम्बर धारक व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के दस्तावेजों को आधार डाटा में अपडेट कर सकता है। इस सुविधा को My Aadhar Portal (https://myaadhaar.uidai.gov.lin.) से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है या निवासी इसका लाभ उठाने के लिये किसी भी नजदीकी नामांकन केन्द्र पर भी जा सकते हैं।

NATIONAL COOPERATIVE UNION OF INDIA

69th ALL INDIA COOPERATIVE WEEK, 2022

वर्ष 2022 का मुख्य विषय
Main Theme for this year (2022):

भारत@75: सहकारिताओं का विकास और भविष्य
India@75: Growth of Cooperatives and Future Ahead

सप्ताह के दिनों की नामावली / Nomenclature of Days:

14-11-2022 : **सहकारिता क्षेत्र में 'इज ऑफ डूइंग बिज़नस', जेम और निर्यात संवर्धन**
Ease-of-doing Business for Cooperatives, GeM, and Export Promotion

15-11-2022 : **सहकारी विपणन, उपभोक्ता, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन**
Cooperative Marketing, Consumers, Processing and Value Addition

16-11-2022 : **सहकारी शिक्षण को मुख्यधारा में लाना, व्यावसायिक प्रबंधन और उन्मुखी प्रशिक्षण**
Mainstreaming Cooperative Education, Professional Management, and Re-orienting Training

17-11-2022 : **नवाचार को बढ़ावा देने में सहकारिता की भूमिका, प्रौद्योगिकी उन्नयन और स्टार्ट–अप को बढ़ावा देना**
Role of Cooperatives in Fostering Innovation, Promoting Start-Ups, and Technology Upgradation

18-11-2022 : **उद्यमिता विकास और सार्वजनिक–निजी–सहकारी भागीदारी को सुदृढ़ बनाना**
Entrepreneurship Development and Strengthening Public–Private–Cooperative Partnership

19-11-2022 : **युवा, महिला, कमजोर वर्ग और स्वास्थ्य के लिए सहकारिता**
Cooperatives for Youth, Women, Weaker Sections, and Health

20-11-2022 : **वित्तीय समावेशन, पैक्स का डिजिटलीकरण और सुदृढ़ सहकारी डेटाबेस**
Financial Inclusion, Digitalization of PACS and Strengthening Cooperative Database

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।